

सहकारिता विभाग  
उत्तराखण्ड



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या-3

विनिश्चय प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम  
निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड,

## विवाद एवं उनका निपटारा

- सहकारी समिति के संघटन, प्रबन्ध अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्डल नियुक्ति की व्यवस्था ।
- समिति/वादी द्वारा भेजे जाने वाले निम्नांकित प्रपत्र –
- विवाद के निस्तारण या वसूली के सम्बन्ध में पूर्व में कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व साक्ष्य
- वाद प्रस्तुत करने हेतु लिये गये निर्णय की प्रति/प्रस्ताव ।
- प्रार्थना-पत्र ।
- विवाद से सम्बन्धित पुष्ट साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां ।
- लेखाशीर्षक "0425-सहकारिता-800-अन्य प्राप्तियां- 06-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां " के अन्तर्गत राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में जमा वाद शुल्क ( मूल्यांकित धनराशि का 1 प्रतिशत) के जमा चालान की प्रति ।
- 2,00,000.00 रु० तक के वाद जिला सहायक निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 2,00,000.00 रु० से 5,00,000.00 तक के वाद उप निबन्धक, सहकारिता के अधिकारिता में ।
- 5,00,000.00 रु० से 10,00,000.00 तक के वाद संयुक्त निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 10,00,000.00 रु० से 15,00,000.00 अधिक के वाद अपर निबन्धक के अधिकारिता में ।
- 15,00,000.00 से अधिक निबन्धक के अधिकारिता में ।

## सहकारी समितियों एवं सहकारिताओं का निबन्धन

### (अ) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 के अर्न्तगत –

- निबन्धन हेतु कम से कम 10 व्यक्ति जो प्रस्तावित समिति के प्रारम्भिक सदस्य होंगे ।
- गठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0) आर्गनाईजर होंगे ।
- निबन्धन हेतु निबन्धन प्रार्थना-पत्र एवं उपविधियां निर्धारित शुल्क 500.00 रु0 राजकीय कोषागार में जमा करने पर जिला सहायक निबन्धक के कार्यालय से प्राप्त होंगे ।
- निबन्धन हेतु निम्नांकित प्रपत्र विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह0) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायेंगे ।
- प्रस्तावित समिति के सदस्यों द्वारा की गयी बैठकों की कार्यवृत्तियां ।
- निबन्धन प्रार्थना पत्र एवं उपविधियों के सम्बन्ध में निर्धारित लेखाशीर्षक (0425- सहकारिता- 800-अन्य प्राप्तियां -06- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां) के अर्न्तगत राजकीय कोषागार /स्टेट बैंक में जमा शुल्क मु0 500.00 के चालान की प्रति ।
- निबन्धन प्रार्थना पत्र ।
- आर्गनाईजर / इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट ।
- प्रतिमान उपविधियों की तीन प्रतियां ।
- जिला सहकारी बैंक में जमा अंशधन की रसीद ।
- सदस्यों के फोटो एवं निवास का पहचान ।
- प्रस्तावित समिति के कार्यालय व अभिलेखों की व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
- प्रतिमान उपविधियों में निबन्धक द्वारा किये जाने वाले छोटे मोटे संशोधनों को किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समिति के मुख्य प्रवर्तक का सहमति पत्र ।
- निबन्धन प्रमाण-पत्र उप निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जायेगा ।
- 

### (ब) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत :-

- सहकारिताओं के गठन/पंजीकरण हेतु कम से कम 7 व्यक्तियों अथवा 2 सहकारिताओं का होना आवश्यक ।
- सहकारिताओं के संगठन हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी पर्यवेक्षक/सहायक विकास अधिकारी (सह0) आर्गनाईजर होंगे ।
- सहकारिता के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्रादि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की अनुसूची में उल्लिखित हैं ।
- अधिनियम की अनुसूची (ख) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर संगम ज्ञापन एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद की तीन-तीन प्रतिलिपियां ।
- प्रार्थना-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क ।

- राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में लेखाशीर्षक ( 0425—सहकारिता —800— अन्य प्राप्तियां —06 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां ) के अर्न्तगत निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम 500 /रु० तथा अधिकतम 10,000/रु० या साम्य पूजी के 1 प्रतिषत के बराबर ) जमा चालान की प्रति ।
- सदस्यों के फोटो एवं निवास का प्रमाण—पत्र ।
- सम्बन्धित तहसील के तहसील स्तर पर कार्यरत अपर जिला सहकारी अधिकारी अथवा राज्य के निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धन प्रमाण—पत्र निर्गत किये जायेंगे ।

### (स) परिवर्तित की जानी वाली सहकारिताओं का पंजीकरण—

- अधिनियम के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के अर्न्तगत पूर्व पंजीकृत सहकारी समितियों को सहकारिताओं में परिवर्तित कर पंजीकरण किये जाने की भी व्यवस्था ।
- पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रपत्र निबन्धक, सहकारी समितियां ,उत्तरांचल को भेजे जायेंगे ।
- सम्बन्धित सहकारी समिति के पदाधिकारियों/ सदस्यों द्वारा अधिनियम की अनुसूची (घ) में निर्दिष्ट प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र एवं अनुसूची (च) में निर्दिष्ट संगम अनुच्छेद तीन—तीन प्रतियों में ।
- राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में लेखा शीर्षक (0425—सहकारिता—800— अन्य प्राप्तियां —06— अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां) के अर्न्तगत निर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क (न्यूनतम 500/— तथा अधिकतम 10000/रु० या साम्य पुजी के 1 प्रतिषत के बराबर) जमा चालान की प्रति ।
- प्रस्तावित सहकारी समिति के पदाधिकारियों के फोटो एवं निवास का प्रमाण—पत्र ।
- निबन्धन हेतु प्रपत्र विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (सह०) के स्तर से जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायेंगे

### सहकारी समितियों में निर्वाचन

#### सहकारी समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्य—

- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने की सूचना कार्यकाल की समाप्ति के 4 माह पूर्व निबन्धक को प्रेषित करना ।
- प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु समिति की सदस्यता, राजस्व क्षेत्र आदि का विवरण निबन्धक को भेजना ।
- 4 माह पूर्व की सदस्यता सूची ।
- निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली मतदाता सूची तैयार करना ।
- निर्वाचन अधिकारी के साथ आवश्यक निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन आदि सम्पादित करना ।
- समयान्तर्गत निर्वाचन परिणामों की सूचना निबन्धक को भेजना ।

#### जिला सहायक निबन्धक तथा उप निबन्धक/निबन्धक के स्तर पर किये जाने वाले कार्य—

- निर्वाचन तिथि का निर्धारण (निबन्धक/निर्वाचन प्राधिकारण के स्तर पर )
- नियमानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण एवं उनका प्रकाशन ।
- निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करवाना ।
- निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कराना ।

### निर्वाचन के स्तर

#### प्रारम्भिक समितियों में संचालक मण्डल का गठन

- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित

#### केन्द्रीय समिति

- प्रारम्भिक सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची ।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित

#### शीर्ष समितियां

- सदस्य समितियों से नामित सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय का गठन एवं मतदाता सूची ।
- सामान्य निकाय के सदस्यों से संचालक मण्डल का गठन
- संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन
- अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
- महिला अनु0जाति/जन जाति हेतु पद आरक्षित